अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को जाति-प्रमाणपत्र दिया जाना

4713. **श्री राम विलास पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को दिल्ली में जाति-प्रमाणपत्र पाने में बड़ी कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो जाति-प्रमाणपत्र देने के क्या नियम हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख). संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951 के उपबन्धों के अधीन दिल्ली के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट जातियों के व्यक्तियों और वहां के निवासी को ही दिल्ली के सक्षम प्राधिकारियो द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र दिये जा सकते हैं। "निवासी" शब्द का अर्थ राष्ट्रपति के आदेश के अधिसूचित होने की तारीख को किसी व्यक्ति के स्थाई निवास स्थान से है जिसमें उसके राज्य/संघ शासित क्षेत्र के संबंध में उसकी जाति/जनजाति विनिर्दिष्ट की गई है। चूंकि दिल्ली के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां 20-9-1951 को अधिसूचित की गई थीं, अतः कोई व्यक्ति जो उस तारीख के बाद दिल्ली में आया था, दिल्ली की अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता। दिल्ली के सम्बन्ध में कोई अनुसूचित जनजातियां विनिर्दिष्ट नहीं है।

Corrugated Medium Paper

4714. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the paper industry is facing crisis specially in regard to corrugated medium paper ;

(b) will this crisis continue for a long time; and

(c) what steps the Government propose to take to solve this problem ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI) : (a) Government have not received any report that the paper industry is facing crisis in regard to corrugated medium paper.

(b) and (c) . Do not arise..

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णयों का क्रियान्वयन

4715. **श्री राम प्रसाद देशमुख :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय/विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्ष 1977 में कब-कब बैठकें हुई और इन बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिये गये हैं;

(ग) कितने निर्णयों को अब तक पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया हैं; और

(घ) बाकी निर्णयों को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मायती) : (क) से (घ). जी, हां। औद्योगिक विकास विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1977 में दो बैठकें दिनांक 5-5-77 और 18-10-77 को हुई। इसके प्रमुख निर्णय अनुभागों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को तैनात करने, हिन्दी टाइपराइटरों का सम्भरण